Out of court settlements of disputes

*95. SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI :

DR. MURLI MANOHAR JOSHI :

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether DDA had in 1992 invited representations from parties for out of court settlements of disputes ;

(b) if so, the number of representations received for out of court settlements ;

(c) what is the mechanism set up by DDA for the consideration of such representations and what is the number of cases that have been decided ; and

(d) the number of cases in which no action has been taken and by when all the cases are likely to be decided ?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI SHEILA KAUL) : (a) Yes, Sir. Public notice in newspapers inviting representations was issued in 1991.

(b) 217 persons had submitted representations till 15-7-1993 for out-of-court settlement of cases.

(c) DDA has set up a committee to recommend out-of-court settlement of court cases. The recommendations of the Committee are put to Vice-Chairman or Lieutenant Governor by the concerned administrative department for appropriate decision. The Committee has already made final recommendations in respect of 34 cases.

(d) Recommendations are yet to be made in respect of 183 cases. Taking into consideration the complex nature of cases, it is not possible to fix any time limit for final disposal of such cases.

Damages due to floods in Punjab

*96. SHRI JAGIR SINGH DARD :

SHRI VIRENDRA KATARIA :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the Central Government have received any report from the Punjab Government on the loss of life, property and crops etc., caused by the recent floods in Punjab ;

(b) if so, what are the details thereof ;

(c) whether any Central team has gone to Punjab to make on the spot assessment of the damage ;

(d) the details of the Central assistance asked for by the Punjab Government to meet the situation ; and

(e) the nature of assistance actually provided to Punjab Government to meet the situation ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR) : (a) and (b) Government of Punjab has reported the following damages in the wake of recent floods in the State :—

(i) Loss of human lives	321
(ii) Loss of cattle heads	6238
(iii) Damage to crops	15·00 lakh acres (approx.)

The State Government has not yet made a complete assessment of the damage to houses and infrastructure.

(c) and (d) An assessment of damage and requirements of fund to

meet the situation will be made by the Central Team which is currently visiting the State.

(e) Government has released Rs. 21·00 crores representing the full annual Central contribution to the Calamity Relief Fund of Punjab for the year 1993-94. It has also been decided to release in advance Central share of two quarterly instalments of Calamity Relief Fund for the year 1994-95 amounting to Rs. 10·50 crores.

कानपुर शहर के विकास के लिये विश्व बैंक की सहायता

*97. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से कानपुर में शहर विकास परियोजना आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में गत वर्ष का क्या लक्ष्य था और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, नहीं । "नगर विकास" राज्य का विषय है और ऐसी नगर विकास योजनाय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य योजना धन से अथवा बाह्य सहायता से बनाई और चलाई जाती हैं ।

उत्तर प्रदेश में इस समय विश्व बैंक सहायता से एक नगर विकास योजना चल रही है । कानपुर भी 15 लाभ-ग्राही नगरों में शामिल है । 1992-93 के लिए कानपुर के लिये 9.33 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से .75 करोड़ रुपये खर्च किये गये ।

परियोजना की शुरूआत से 1992-93 के अन्त तक, कानपुर के लिये संचयी लक्ष्य 38.3 करोड़ रुपये का था, जिसमें से 33.22 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं ।

रायचूर मध्य प्रदेश में बारूका बांध परियोजना

*98. **श्री अजीत जोगी** :
चौधरी हरि सिंह :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने रायचूर की बारूका बांध (अपर पेरी) परियोजना केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस तारीख को भेजी गई थी ;

(ग) इस परियोजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) बारूका बांध 916.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की संशोधित महानदी जलाशय परियोजना का घटक है । संशोधित परियोजना रिपोर्ट फरवरी 1990 में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी ।

(घ) मूल्यांकन अभिकरणों ने जांच के बाद सिंचाई आयोजना, जल विज्ञान, लागत अनुमानों पर राज्य सरकार को टिप्पणियां भेजी हैं । परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी इन टिप्पणियों की अनुपालना करती है और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करती है ।